भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4647

उत्तर देने की तारीख 29 मार्च, 2023

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

4647. श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य को अब तक आवंटित धनराशि और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एनबीएम के तहत सभी दूरस्थ और ग्रामीण गांवों को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य है और यदि हां, तो वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने का लक्ष्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मिशन के तहत देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की सेवा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के तहत परिकल्पित निवेश को मुख्य रूप से दूरसंचार लाइसेंसधारकों एवं अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा तथा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से सरकार द्वारा जुटाया जाना है। पिछले

तीन वर्षों के दौरान यूएसओएफ की विभिन्न स्कीमों के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य को 42 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत मार्च 2023 तक 100% गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार 93.21% गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है। कुछ गांव अत्यधिक सुदूरवर्ती तथा ग्रामीण इलाकों में हैं और इन गांवों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही वाणिज्यिक सेवाओं के तहत कवर नहीं किया जा सका है। अब 4जी सैचुरेशन स्कीम के तहत दिसंबर 2023 तक सभी गांवों को 4जी सेवाओं से कवर करने की योजना है।

******